उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 4 | अंक 15 | 1-15 अगस्त 2021 | ₹ 20/-

उर्दू प्रेस में तालिबान के इस्लामिक शासन का स्वागत

- भारत में इस्लामिक एकता का प्रयास
- शिंजियांग में रूस और चीन का संयुक्त सैनिक अभ्यास
- संकट का समाधान कर पाएंगे ईरान के नए राष्ट्रपति?
- अहमदियों के खिलाफ अभियान

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–26524018

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

* अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

लव जिहाद विरोधी अभियान पर मुस्लिम समाज में चिंता 04
संघ प्रमुख द्वारा 'भारत वैभव' का विमोचन 06
मोहर्रम के सिलसिले में जारी परिपत्र विवादों में 08
भारत में इस्लामिक एकता का प्रयास 10
दिल्ली में हज हाउस निर्माण पर विवाद 12

विश्व

उर्दू प्रेस में तालिबान के इस्लामिक शासन का स्वागत 14
मलेशिया के प्रधानमंत्री का त्यागपत्र 21
नवाज शरीफ की वीजा अवधि बढ़ाने से ब्रिटेन का इंकार 22
शिंजियांग क्षेत्र में रूस और चीन का संयुक्त सैनिक अभ्यास 23
महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने वाला गिरफ्तार 24

पश्चिम एशिया

क्या संकट का समाधान कर पाएंगे ईरान के नए राष्ट्रपति? 25
संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच तेल सप्लाई समझौता खतरे में 27
सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग के चार आरोपियों को 24 वर्ष की सजा 28
सऊदी अरब में विदेशियों को संपत्ति खरीदने की अनुमति 29
अल्जीरिया में आग से 65 लोग मरे 29

अन्य

मुस्लिम लीग के छात्र प्रकोष्ठ का पुनर्गठन 30
मायावती चुनावों में उतारेंगी 100 मुस्लिम उम्मीदवार 30
मुस्लिम यूनिवर्सिटी गजट में मोदी का चित्र 31
अहमदियों के खिलाफ अभियान 31
इस्लामिक स्टेट का सदस्य जमानत पर रिहा 31

सारांश

अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया है और 20 वर्षों तक खरबों रुपये फूंकने के बावजूद अमेरिका को वहां से दुम दबाकर भागना पड़ा है। बड़ी अजीब बात है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को यह आशा थी कि उसके द्वारा प्रशिक्षित साढ़े तीन लाख अफगान फौज कम–से–कम एक से तीन महीने तक तालिबान को उलझाए रखेंगी। मगर अफगान सेना ने बिना एक गोली चलाए तालिबान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। खास बात यह है कि उन्होंने अमेरिका द्वारा उन्हें दिए गए खरबों डॉलर के अति आधुनिक हथियार भी तालिबान को सौंप दिए हैं। इसके कारण तालिबान की शक्ति में भारी वृद्धि हुई है और उसकी गणना विश्व की अतिआधुनिक अस्त्र–शस्त्रों से लैश सेना में की जा रही है। खास बात यह है कि तालिबान अफगानिस्तान में मासूम लोगों के खून से होली खेल रहे हैं मगर भारत के लगभग सभी उर्दू समाचारपत्र तालिबान की विजय पर खुशियां मना रहे हैं और उसे इस्लाम के इतिहास की सबसे शानदार विजय की संज्ञा दे रहे हैं।

तालिबान की विजय पर जश्न मनाने वाले अधिकांश मुस्लिम नेताओं में भी होड़ लगी हुई है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने तो उनकी तुलना देश के स्वतंत्रता सेनानियों तक से कर डाली है। कश्मीरी मुस्लिम नेताओं में भी तालिबान की विजय पर जश्न मनाने की होड़ लगी हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक पदाधिकारी सज्जाद नुमानी ने भी तालिबान के कब्जे का स्वागत किया था मगर जब पुलिस ने बर्क और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया तो फौरन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना रंग बदल लिया और कहा कि ये सज्जाद नुमानी के व्यक्तिगत विचार हैं जिससे बोर्ड़ का कोई लेना–देना नहीं है। असम में तो मुस्लिम संगठनों ने खुलकर तालिबान की विजय का स्वागत किया। वहां की पुलिस को इस संबंध में 18 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करने पड़े।

पिछले दिनों देश की मुस्लिम राजनीति ने एक नई करवट ली है। दिल्ली में 80 मुस्लिम नेताओं की एक बैठक हुई, जिसमें यह तय किया गया कि 72 फिरकों (मसलकों) में बंटे हुए मुस्लिम समाज को एकजुट किया जाए। खास बात यह है कि इस अभियान की शुरुआत सऊदी अरब के मक्का से हुई है। क्या भारतीय मुस्लिम संगठनों ने भी इस सिलसिले में सऊदी अरब का अनुसरण किया है? हिंदू समाज मुसलमानों के विभिन्न संगठनों के बीच भीषण मतभेदों से अवगत नहीं है। इस बात को कौन नहीं जानता कि पिछले डेढ़ सौ वर्षों से भारत के अनेक प्रमुख नगरों में शिया सुन्नी दंगे होते रहे हैं। देवबंदियों की नजर में मजारों पर हाजिरी देना कुफ्र है तो बरेलवी और सूफी इसे इस्लाम का अंग मानते हैं। गत एक शताब्दी से देवबंदी और बरेलवी एक दूसरे के खिलाफ फतवे जारी करके एक दूसरे को काफिर और कुफ्र की संज्ञा देते रहे हैं। अहमदियों को तो मुसलमान तक मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हाल ही में इस संदर्भ में आंध्र प्रदेश में मामला पुलिस तक भी जा पहुंचा है। इससे पूर्व भी अनेक बार मुसलमानों की विभिन्न विचारधाराओं के फिरकों को एकजुट करने के प्रयास होते रहे हैं। हालांकि उसमें अभी तक कोई विशेष कामयाबी नहीं मिली है।

हाल ही में नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 'भारत वैभव' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की गई है, जिसका विमोचन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने एक समारोह में किया था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि संपूर्ण भारत कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। जब कोई आक्रमणकारी देश पर आक्रमण की कोशिश करना शुरू करता था तो उसी दिन से उसे उखाड़ने की शुरुआत हो जाती थी। उन्होंने कहा कि भारत का गौरव उसके अपने मौलिक ज्ञान में है और इसे दूसरे देश की नकल करने की जरूरत नहीं। भारत अपनी ज्ञान परम्परा को पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए पैदा हुआ है।

राष्ट्रीय

लव जिहाद विरोधी अभियान पर मुस्लिम समाज में चिंता

कुछ हिंदू संगठनों द्वारा गत कुछ समय से लव जिहाद के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा था उसके खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने भी जवाबी अभियान छेड़ दिया है।

इंकलाब (5 अगस्त) के अनुसार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुस्लिम लड़कियों द्वारा गैर मुस्लिम लड़कों के साथ विवाह की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के खिलाफ गहरी चिंता प्रकट की है और मुस्लिम लड़कियों के अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे अपनी लड़कियों पर गहरी नजर रखें ताकि वे गुमराह न हों। बोर्ड के कार्यकारी महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा है कि मुस्लिम लड़कियों की शादी मुस्लिम लड़कों से ही हो सकती है। इसी तरह मुस्लिम लड़के भी गैरमुस्लिम लड़कियों से शादी नहीं कर सकते। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में सतर्कता बरतें। इसके अतिरिक्त उन्होंने मुस्लिम उलेमा और मस्जिदों के इमामों से अनुरोध किया है कि वे युवा वर्ग और विशेष रूप से युवतियों और किशोरियों के साथ इस संदर्भ में अधिक–से–अधिक बैठकें आयोजित करें ताकि मुस्लिम लड़के और लड़कियां गैर मुसलमानों के चंगुल में न फंसें। मौलाना रहमानी ने अपने बयान में कहा है कि इस्लाम में निकाह के मामले में इस बात को जरूरी करार दिया गया है कि एक मुस्लिम लड़की का निकाह सिर्फ मुस्लिम लड़के से ही हो सकता है। इस तरह मुस्लिम लड़का भी किसी गैर मुस्लिम से निकाह नहीं कर सकता। अगर इस तरह का कोई निकाह होता है तो वह शरा की दृष्टि से गलत होगा।

दफ्तरों के कार्य क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के एक साथ काम करने के कारण अंतरधार्मिक विवाह की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसी अनेक घटनाएं सामने आई हैं जिसमें देखा

गया है कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुसलमानों के साथ चली गईं और उन्हें बाद में बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहां तक कि उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। इसलिए यह जरूरी है कि मुस्लिम विद्वान और इमाम युवा वर्ग में दीनी जागरूकता पैदा करें ताकि अंतरधार्मिक विवाह को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए यह ज्रूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों की दीनी शिक्षा का प्रबंध करें और लड़के और लड़कियों के मोबाइल पर गहरी नजर रखें ताकि वे गुमराह न हों। मुसलमानों को इस बात का प्रयास करना चाहिए कि वे अपनी बेटियों को केवल लड़कियों की स्कूलों और कॉलेजों में ही शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजें। जो लोग अदालत में जाकर विवाह करते हैं उन्हें अदालतों द्वारा विवाह के इच्छुक व्यक्तियों की सूचना काफी पहले जारी कर दी जाती है। दीनी संगठनों, धार्मिक नेताओं, अध्यापकों और मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों का यह कर्तव्य है कि अगर उन्हें किसी ऐसे मामले की जानकारी मिलती है तो वे संबंधित लड़की और लड़के के घर जाकर उसे समझा–बूझाकर अंतरधार्मिक विवाहों से दूर रखें और उन्हें समझाएं कि इस तरह के प्रेम विवाह विफल रहते हैं और उनकी पूरी जिंदगी हराम बन जाती है। उन्होंने कहा कि यह भी सूचना में आया है कि जब लड़कियों की शादी कुछ समय तक नहीं हो पाती तो वह गुमराह हो जाती हैं और गैरमुसलमानों के चक्कर में फंस जाती हैं। इसलिए यह जरूरी है कि समय पर मुसलमान लड़के या लड़कियों का विवाह किया जाए। ताकि इस तरह की घटनाएं न हों।

इंकलाब (9 अगस्त) में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार मुस्लिम लड़कियां गैर मुसलमानों के चंगुल में फंसती जा रही हैं, जिसके कारण दोनों सम्प्रदायों में तनाव पैदा हो रहा है। एक ओर तो लव जिहाद का आरोप लगाया जाताहै और दूसरी ओर एक विशेष समाज के लोग इस बात का प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों को विवाह के लिए चंगुल में फंसाया जाए। भगवा परिवार के कुछ संगठन इस तरह के अभियान में खास रुचि ले रहे हैं। मुसलमानों में गैर मुसलमानों के साथ विवाह करने का जो रूझान बढ़ रहा है उसके लिए समाजसेवियों ने अभिभावकों द्वारा बच्चों का गलत पालन पोषण के साथ–साथ मोबाइल और सोशल मीडिया को भी दोषी ठहराया है। विख्यात वकील शाहिद अली का कहना है कि हालात दिन–प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों के साथ गैर मुस्लिम लड़कों के विवाह का रूझान बढ़ रहा है। उन्होंने इसके तीन कारण बताए हैं। पहला कारण यह है कि मुसलमानों में भय का वातावरण पैदा किया जा रहा है जिसके कारण लड़कियां यह महसूस करती हैं कि अगर उन्होंने गैर मुस्लिम लड़कों के साथ विवाह कर लिया तो उनकी जान व माल सुरक्षित हो जाएगी। दूसरा कारण सहशिक्षा है जिसके कारण बच्चे मां–बाप के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। यही कारण है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पहली से लेकर बी.ए. तक लड़के और लड़कियों की शिक्षा अलग–अलग है। तीसरा कारण यह है कि जो मुस्लिम लड़के मुस्लिम लड़कियों को नजरअंदाज करके गैरमुसलमान लड़कियों से शादी करते हैं वे मुस्लिम लड़कियों का हक मारते हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सायरा खान का मतहै कि कुछ संगठन जानबूझकर लड़कों को इस बात के लिए प्रेरित करते हैं किवे मुस्लिम लड़कियों को अपनी जाल में फंसाएं। हमदर्द नेशनल फाउंडेशन के शौकत मुफ्ती का कहना है कि इस तरह की घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि नई पीढ़ी इस्लाम से दूर होती जा रही है। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों की मानसिकता इस्लामिक होनी

चाहिए ताकि वे गुमराह न हों और अपने धर्म पर टिके रहें।

कई उर्दू समाचारपत्रों ने इस अभियान को गति देने के लिए विभिन्न स्थानों से समाचार प्रकाशित करने का सिलसिला भी शुरू किया है।

दैनिक इंकलाब ने 8 अगस्त के संपादकीय में कहा है कि शादियों को साम्प्रदायिक रंग में रंगने का काम भाजपा की राज्य सरकारों ने किया है। उन्होंने आरएसएस और उसके सहायक संगठनों द्वारा लव जिहाद के झूठे प्रचार को पहले सरकारी सच बताया और फिर बिल्कुल एकतरफा कानून बना दिया। जैसा कि आप जानते हैं बीजेपी की सरकार के आने के बाद झूठे प्रोपगंडा की जो दुकानें जगह–जगह खुल गई हैं उन्होंने लव जिहाद के मनगढंत शब्द को खूब उछाला और यहां तक मशहूर किया कि हिंदू लड़कियों से शादी करने वाले मुसलमान लड़कों को मुस्लिम संगठन कई–कई लाख रुपये देते हैं। आपको याद होगा कि 2017 में विभिन्न न्यूज चैनलों पर हिंदू जागरण मंच की ओर से इस प्रचार को खूब हवा दी गई कि अगले छह महीने में 2100 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू परिवारों का बहु बनाया जाएगा। मगर झूठे का मुंह हमेशा काला ही होता है। वह 200 तो छोड़ो 21 मुस्लिम लड़कियों को भी अपने घर की बहु नहीं बना सके। इसके बाद 2018 में 14 अगस्त को हिंदू युवा मोर्चा नामक एक संगठन ने यह घोषणा की कि जो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादी करेंगे उनको ढ़ाई लाख रुपया नकद, छह महीने तक खाना–पानी और सुरक्षित आवास दिया जाएगा। मगर कोई भी हिंदू लड़का ढ़ाई लाख रुपये लेने नहीं आया। मुसलमानों के खिलाफ एकतरफा कानून बनाए जाने की प्रक्रिया होना स्वाभाविक था। इसलिए अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मुसलमानों के लिए एक एडवायजरी जारी करनी पड़ी, जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम लड़कों और लड़कियों पर माता–पिता कड़ी नजर रखें। उनके मोबाइल चेक करें। लड़कियों को गर्ल्स स्कूल में पढ़ाएं और मैरिज रजिस्ट्रार के दफ्तर में अगर किसी विवाह के इच्छुक लड़के या लड़कियों की तस्वीर लगी हो मुस्लिम धार्मिक नेता उन्हें जाकर समझाएं। हमारे विचार में मुस्लिम लड़के और लड़कियों के समस्याओं का समाधान यह है कि वे विवाह शादी में हिंदुस्तानी रस्मो–रिवाज को छोड़कर विशुद्ध इस्लामिक शादियां करें, जिसमें दहेज का नामोंनिशान न हो।

संघ प्रमुख द्वारा 'भारत वैभव' का विमोचन

रोजनामा सहारा (12 अगस्त) के अनुसार नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने डॉ. ओम प्रकाश पांडेय द्वारा लिखित पुस्तक 'भारत वैभव' का विमोचन किया। इस अवसर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रो. गोविंद प्रसाद शर्मा आदि उपस्थित थे।

इस अवसर पर मोहन भागवत ने अपने उदबोधन में कहा कि संपूर्ण भारत कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। जब कोई आक्रमणकारी देश पर आक्रमण की कोशिश करना शुरू करता था तो उसी दिन से उसे उखाड़ने की शुरुआत हो जाती थी। उन्होंने कहा कि भारत का गौरव उसके अपने प्राचीन ज्ञान में है और इसे दूसरे देश की नकल करने की जरूरत नहीं। भारत अपनी ज्ञान परम्परा को पूरी दुनिया के साथ साझा करने के लिए पैदा

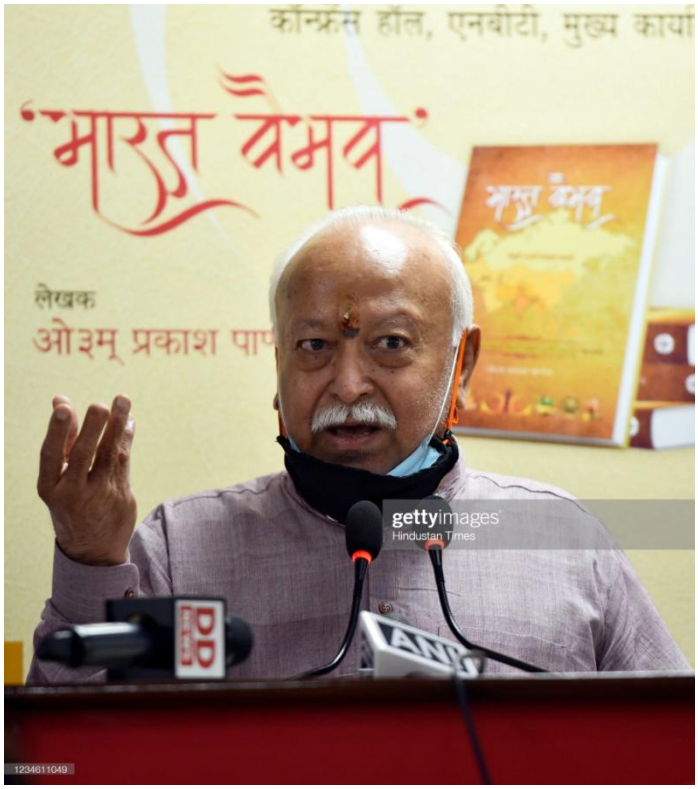

हुआ है। भारत के बारे में ज्ञान के अथाह सागर का सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद और व्यापक रूप से प्रचारित और प्रसारित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझसे अक्सर यह पूछा जाता है कि हम चीन या अमेरिका या फिर रूस की तरह क्यों नहीं कर सकते? मैं कहूंगा कि हमें किसी और देश की नकल क्यों करनी है? हमें उनकी तरह क्यों बनना है? हमें अपने तरीके से काम करना चाहिए। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख ने कहा कि आज हमें शिक्षा नीति के जरिए फिर से भारतीय मूल्यों की ओर लौटने की जरूरत है। जब हम अपने मूल्यों की ओर लौटते हैं तो उस पर उल्टी सीधी चर्चाएं भी होती हैं। इस पर भी होंगी। उन्होंने कहा कि हम अपने ज्ञान और संस्कृति के कारण कट्टरता से दूर हैं। यही कारण है कि हम कभी किसी पर आक्रमण करने नहीं गए और न ही किसी अन्य देश पर राज करने जाते हैं। हम ज्ञान और संस्कृति के माध्यम से ही दिल जीतते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज, देश या व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। देश में सिकंदर के आने से पहले ही अन्य लोगों द्वारा आक्रमण करने के लिए तांता लगना शुरू हो गया था। सभी आक्रमणों से देश लगातार लड़ता रहा और जीत हासिल करता रहा। इससे कभी भी हमारी संपूर्ण भूमि गुलाम नहीं हुई। जब कोई आक्रमणकारी देश पर आक्रमण करने की कोशिश करता था तो उसी दिन से उसको उखाड़ने की शुरुआत हो जाती थी।

मोहन भागवत का कहना है कि 'स्व गौरव' से बड़ा कोई गौरव नहीं है। भारत का गौरव है उसकी ज्ञान परम्परा। भारत का जन्म ही पूरे विश्व में अपनी ज्ञान परम्परा को बांटने के लिए हुआ है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के वसंतकुंज स्थित कार्यालय में आयोजित इस समारोह में उन्होंने कहा कि इस पुस्तक में आत्मा से लेकर अनात्मा तक का ज्ञान विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। गागर में सागर बांधने वाली इस पुस्तक का अनुवाद राष्ट्र की सभी भाषाओं में किया जाना चाहिए ताकि उसका व्यापक प्रचार हो।

केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि किसी भी राष्ट्र का मनोबल और आत्मबल अपनी संस्कृति के सहारे ही जागृत हुआ है। भारतीय संस्कृति आज भी सनातन है और हमारा यह सामूहिक दायित्व है कि हम इसे जानने की पूरी कोशिश करें। सांसद डॉ. सत्यपाल सिंह ने कहा कि पुस्तक का मूल तत्व एक श्रेष्ठ भारत है और देश को जिस परम वैभव को छूने का निरंतर प्रयास करना चाहिए

उसके लिए यह पुस्तक पहला कदम है। न्यास के अध्यक्ष प्रो. डॉ. गोविंद प्रसाद शर्मा ने कहा कि भारत की ज्ञान परम्परा सबसे प्राचीन है और यह पुस्तक इन्हीं भारतीय मूल्यों को विश्व में पुनः स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगी। पुस्तक के लेखक ओम प्रकाश पांडेय ने भारत वैभव का वर्णन करते हुए कहा कि संस्कृति राष्ट्र रूपी देह की आत्मा होती है और भारत की संस्कृति अपनी गौरवशाली परम्पराओं के साथ आज भी जीवंत है। न्यास के निदेशक युवराज मलिक ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में इस प्रकार का साहित्य और मिलेगा एवं ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में न्यास हमेशा अग्रणी रहेगा।

मोहर्रम के सिलसिले में जारी परिपत्र विवादों में

इंकलाब (3 अगस्त) के अनुसार मोहर्रम के अवसर पर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन की ओर से जारी परिपत्र का मामला दिन–प्रतिदिन तूल पकड़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस सुर्कलर के कई बिंदुओं पर उलेमा और महत्त्वपूर्ण हस्तियों ने सख्त ऐतराज किया है। मजलिस उलेमा–ए–हिंद के महामंत्री मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन करके उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी मुकुल गोयल से माफी की मांग की है और कहा है कि अगर वे ऐसा नहीं करते तो सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने यह भी धमकी दी कि मोहर्रम के अवसर पर होने वाली सभी प्रशासकीय बैठकों का बहिष्कार किया जाएगा। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डॉ. डी.के. ठाकुर ने मौलाना कल्बे जवाद नकवी से उनके निवास स्थान पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। नकवी ने कहा कि मोहर्रम हमारा बहुत पाक और पवित्र महीना है। इसमें अत्यंत शांतिपूर्ण और पवित्र कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पुलिस प्रशासन ने यह सर्कुलर जारी करके मोहर्रम और शियाओं की छवि को खराब करने की कोशिश की है और अत्यंत अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। पुलिस प्रशासन ने सर्कुलर में यह लिखा है कि मोहर्रम के जुलूसों में 'तबर्रा' पढ़ा जाता है। जिस पर मुसलमानों के कई अन्य फिरकों को आपत्ति होती है। मोहर्रम के जुलूसों में शरारती तत्व भाग लेते हैं जो दूसरे सम्प्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए 'तबर्रा' लिखते हैं। मौलाना ने कहा कि यह बिल्कुल गलत है और मोहर्रम को बदनाम करने की साजिश है। मोहर्रम गम का महीना है, जिसमें इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत का शोक मनाया जाता है। यह कोई जश्न नहीं है। इसलिए इसमें किसी भी तरह के हंगामे और बदतमीजी का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

उन्होंने कहा कि शिया सुन्नी दोनों ही शांतिपूर्ण ढंग से मोहर्रम का गम मनाते हैं और इसमें कई बार हिंदू भी शामिल होते हैं, जिसके बारे में पुलिस महानिदेशक को मालूम होना

चाहिए था। इस सर्कुलर को पढ़कर ऐसा महसूस होता है कि जैसे शिया और मोहर्रम को बदनाम करने की सोची–समझी साजिश हो। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि एक भी ऐसी घटना पूरे हिंदुस्तान में दिखाइये जहां मोहर्रम में किसी के साथ छेड़छाड़ हुई हो। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद अब तक जारी सरकारी सर्कुलर में इस तरह की भाषा का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी शिया–सुन्नी और हिंदू संगठनों से अपील की कि जब तक यह परिपत्र वापस नहीं लिया जाता हम पुलिस प्रशासन द्वारा बुलाई गई किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे।

समाचारपत्र के अनुसार पुलिस कमिश्नर डी.के. ठाकुर ने मौलाना से मुलाकात करने के बाद बताया कि यह परिपत्र पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है। इस पर मौलाना ने कहा कि तब तो यह और भी गलत बात है। इस तरह के सर्कुलर जारी करके पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को गलत संदेश दिया जा रहा है। पुलिस आयुक्त ने कहा कि वे इस संदर्भ में पुलिस के उच्चाधिकारियों को मौलाना की भावनाओं से अवगत कराएंगे।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार में पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रशांत कुमार ने कहा कि इस तरह का सर्कुलर हर बार जारी किया जाता है और इसका लक्ष्य किसी धर्म या मजहब का अपमान करना नहीं, न ही उससे संबंधित श्रद्धालुओं की भावनाओं को चोट पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे उच्च पुलिस अधिकारियों से बातचीत करके कोई रास्ता निकालेंगे।

दिल्ली की शिया जामा मस्जिद में आयोजित एक कार्यक्रम में शिया नेताओं ने यह मांग की कि इस परिपत्र में जो भाषा इस्तेमाल की गई है उससे मुसलमानों के विभिन्न फिरकों में मतभेद बढ़ सकते हैं। उन्होंने मांग की कि इस परिपत्र को फौरन वापस लिया जाए और एक अन्य परिपत्र जारी किया जाए। मौलाना मोहसिन अली नकवी ने कहा कि मोहर्रम के दौरान कोरोना महामारी के सिलसिले में जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका शिया पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस परिपत्र के कुछ अंशों पर हमें आपत्ति हैं इनको फौरन हटा लिया जाना चाहिए।

इंकलाब के संपादक शकील शम्सी ने 3 अगस्त के अंक में अपने संपादकीय में उत्तर प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाया है कि वह मुसलमानों में फूट डालने का प्रयास कर रही है। पहले प्रशासन ने इस कार्य के लिए वसीम रिजवी का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा है कि वसीम रिजवी अकेला नहीं है पूरा एक इस्लाम दुश्मन गिरोह इसके साथ है, जिसकी जड़ें नागपुर तक फैली हुई हैं। यही कारण है कि उनके खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मोहर्रम के संबंध में जो सर्कुलर जारी किया है वह भी इसी अभियान का एक हिस्सा है। सवाल यह उठता है कि सरकारी कागज को वायरल क्यों किया गया? इस सर्कुलर में खुलकर देवबंदी, अहले हदीस फिरकों के बरेलवी, सूफी और शिया फिरकों के मतभेदों से संबंधित ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनका कोई वजूद नहीं है।

संपादक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कभी शिया–सुन्नी दंगे नहीं हुए। हां, लखनऊ में ही इन दोनों के बीच झगड़ा होता रहा है। हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि पूरे सूबे की पुलिस को यह क्यों बताया जा रहा है कि मोहर्रम के दौरान शिया, बरेलवी और सूफी मुसलमान ताजिया निकालते हैं। इस पर अहले हदीस और देवबंदी आपत्ति करते हैं। लखनऊ में 40–50 वर्ष पहले हुए शिया सुन्नी झगड़ों का पूरे प्रदेश में जिक्र किए जाने का क्या उद्देश्य है? संपादक ने यह स्वीकार किया है कि 80 के दशक के प्रारम्भ तक शिया–सुन्नी दंगों का

सिलसिला जारी रहा। मगर बाद में अयोध्या विवाद और शाहबानो केस के बाद वहां पर मुसलमान आपस में कभी नहीं टकराए। संपादक ने इस परिपत्र को वापस लेने की मांग की है।

अवधनामा (8 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि शियाओं में इस परिपत्र के कारण जो नाराजगी पैदा हुई थी उसके बाद पुलिस महानिदेशक ने मौलाना नकवी से माफी मांग ली है और उन्होंने कहा कि भविष्य में इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे शियाओं की भावनाएं आहत हों। डीजीपी ने कहा कि यह परिपत्र खुफिया थी। इस स्पष्टीकरण के बाद शिया नेताओं ने प्रशासन की बैठकों का बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया। शिया नेताओं ने इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आतिफ रशीद से भी मुलाकात की है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने विवादित गाइडलाइन को जारी करने पर उत्तर प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया है और उनसे इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है।

अवधनामा ने 10 अगस्त के एक अन्य संपादकीय में कहा है कि एक बार फिर मोहर्रम कोरोना के साए में मनाया जा रहा है। नई गाइडलाइन के तहत मोहर्रम में कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा। न ही ताजिया को दफन करने के लिए भीड़भाड़ लागई जा सकती है। बल्कि दो तीन लोग ही ताजिए को दफन करने के लिए जा सकते हैं। मोहर्रम के सिलसिले में जो मजलिसें आयोजित होंगी, उनमें 50 से अधिक लोग भाग नहीं लेंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। लखनऊ में धारा 144 लागू की गई है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गस्त बढ़ा दी गई है। पूरे देश में मोहर्रम के मजलिसों का आयोजन कोविड गाइडलाइन के तहत ही किया जा रहा है।

अवधनामा (14 अगस्त) के अनुसार मौलाना कल्बे जवाद नकवी ने पुलिस और प्रशासन से अनुरोध किया है कि मोहर्रम में किसी तरह की सख्ती न की जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने काले झंडे लगाने पर जो प्रतिबंध लगाया है वह उचित नहीं है।

भारत में इस्लामिक एकता का प्रयास

आमतौर पर यह समझा जाता है कि मुसलमानों में किसी तरह के फिरके या मतभेद नहीं हैं। हालांकि जमीनी हकीकत यह नहीं है। मुस्लिम विद्वान डॉ. जाफर रजा के अनुसार मोटे तौर पर मुसलमान 72 फिरकों (मसलकों) में विभाजित हैं।

इंकलाब (9 अगस्त) के अनुसार ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के महामंत्री और इंस्टिट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्ट्डीज (आईओएस) के अध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मंजूर आलम की ओर से जामिया नगर में इत्तेहादुल मिल्लत बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें जमीयत उलेमा के अध्यक्ष सैयद अरशद मदनी, जमात–ए–इस्लामी के अमीर सआदतुल्लाह हुसैनी, दारूल उलूम देवबंद के प्रबंधक मुफ्ती अबुल कासिम नुमानी, शिया आलम–ए–दीन और मजलिस उलेमा–ए–हिंद के महामंत्री मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी, उलेमा व मिशाइख बोर्ड के प्रमुख मौलाना सैयद अशरफ किछौछवी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महामत्री मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, शिया विद्वान खालिद रसीद फिरंगी महली आदि प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया। बैठक के बाद इंकलाब के संवाददाता से बातचीत करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मैं दारूल उलूम देवबंद के हवाले से यह बात कहता हूं

कि उसका एक मसलक है, उसके आधार पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो देवबंदियों को काफिर करार देते हैं। लेकिन दारूल उलूम देवबंद ने किसी के खिलाफ काफिर होने का फतवा जारी नहीं किया। मगर अगर कोई व्यक्ति शरिया का विरोध करता है तो हम उसकी आलोचना करते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरात के अध्यक्ष नावेद हामिद ने कहा कि इस बैठक में यह तय हुआ है कि मुसलमानों में विभिन्न फिरकों अर्थात मसलकों में जो मतभेद हैं उन्हें दूर किया जाए। इसके लिए माहौल बनाना चाहिए। सारे मुसलमानों की उम्मत को एक जगह इकठा होना चाहिए।

मक्का से शुरुआत

भारतीय मुसलमानों के विभिन्न फिरकों में एकता के जो प्रयास शुरू हुए हैं उसकी शुरुआत मक्का से हुई है।

इंकलाब (7 अगस्त) के अनुसार मक्का की मुस्लिम वर्ल्ड लीग की ओर से मिल्लत एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वस्तर के मुसलमानों के विभिन्न फिरकों के 80 नेताओं ने भाग लिया। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महामंत्री डॉ. मोहम्मद अल–ईस्सा ने अपने उदघाटन भाषण में कहा कि एकता के प्रयासों की शुरुआत शिया और सुन्नियों के बीच होनी चाहिए। अगर इस्लाम और 'उम्मा' को जिंदा रखना है तो हमें आपसी मसलकी मतभेद भूलकर एकजुट होना होगा। मुस्लिम वर्ल्ड लीग वेबसाइट के अनुसार मक्का में इस तरह का यह पहला अधिवेशन है। इससे पहले 2006 में भी ओआईसी ने इस तरह का प्रयास किया था। यह सम्मेलन उन्हीं प्रयासों की अगली कड़ी है।

जमीयत उलेमा के महामंत्री मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी ने कहा है कि वे मुसलमानों के विभिन्न मसलकों को एकजुट करने के लिए मौलाना शाह अजमल फारूक नदवी और मोहम्मद आलम के साथ देशव्यापी भ्रमण कर रहे हैं। शीघ्र ही दिल्ली में एक इत्तेहाद मिल्लत कांफ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसके लिए सभी मुस्लिम संगठनों की ओर से संयुक्त निमंत्रण दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य से 25 प्रमुख नेताओं की एक समिति बनाई गई है,जिसके संयोजक खालिद सैफुल्लाह रहमानी,

सह संयोजक मौलाना अनीस उर रहमान कासमी और मौलाना शाह अजमल फारूक नदवी हैं। उन्होंने कहा कि यह तय किया गया कि मुसलमानों की ओर से कोई ऐसी बात न की जाए या कोई ऐसा मामला न उठाया जाए जिससे दूसरे मसलक के लिए परेशानी हो। मिल्लत–ए–इस्लामिया की समस्याओं के लिए हमें मिलजुलकर प्रयास करना चाहिए। हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि मुस्लिम दुश्मन संगठनों की ओर से मुसलमानों के विभिन्न फिरकों को आपस में लड़वाने के जो प्रयास किए जा रहे हैं हम उनके जाल में न फंसें।

दिल्ली में हज हाउस निर्माण पर विवाद

दिल्ली सरकार द्वारा द्वारका के सेक्टर 22 में हज हाउस का निर्माण विवादों में उलझ गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस भवन की आधारशिला 2008 में दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने रखी थी। इसके बाद यह मामला खटाई में पड़ गया। 2018 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसके निर्माण के लिए 94 करोड़ रुपये मंजूर किए। कहा जाता है कि इन दिनों इस हज हाउस का निर्माण चल रहा है। इससे पूर्व तुर्कमान गेट के समीप अस्थाई रूप से हज हाउस का निर्माण किया गया था। क्योंकि तुर्कमान गेट वाली जगह हाजियों की बढ़ती हुई संख्या के लिए कम थी इसलिए तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने द्वारका में नए हज हाउस के निर्माण का फैसला किया था।

मुंबई उर्दू न्यूज (8 अगस्त) के अनुसार इस हज हाउस के निर्माण के खिलाफ एक महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें कट्टरवादी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया था। इसमें भारतीय जनता पार्टी (दिल्ली) के अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल हुए थे। इस महापंचायत का उद्देश्य सरकार को यह बताना था कि अगर उनकी मर्जी के बिना द्वारका में हज हाउस का निर्माण हुआ तो यहां साम्प्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। समाचारपत्र ने लिखा है कि इससे पूर्व भी द्वारका में हज हाउस बनाने का विरोध मुस्लिम

संगठनों ने किया था, जिसके कारण यह योजना खटाई में डाल दी गई थी। मुस्लिम संगठनों का कहना था कि दिल्ली हज कमेटी के दफ्तर के साथ ही हज हाउस का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि द्वारका शहर से काफी दूर है। दिल्ली पुलिस ने हज हाउस का विरोध करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। द्वारका जिला के पुलिस उपायुक्त एसके मीणा ने बताया कि जुमा के दिन सेक्टर 22 में जो सभा हुई थी उसमें कोरोना महामारी के नियमों का उल्लंघन किया गया था। इसलिए इसके आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनका पता लगाने के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की सहायता ली जा रही है।

भाजपा नेता आदेश गुप्ता का कहना है कि इसे खाप पंचायतों की इच्छा के विरुद्ध बनाया जा रहा है। उनकी मांग है कि प्रस्तावित हज हाउस के लिए अलॉट की गई भूमि पर अस्पताल या स्कूल बनाया जाए। भाजपा ने केजरीवाल सरकार को सुझाव दिया है कि वह किसानों की भूमि पर हज हाउस बनाने की बजाय वक्फ बोर्ड की खाली पड़ी जमीनों पर हज हाउस बनाए। आदेश गुप्ता ने यह दावा किया कि 2007 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने यहां पर हज हाउस बनाने की योजना बनाई थी और फरवरी 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने इसकी आधारशीला रखने का जब प्रयास किया था तो उसका विरोध किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल अपने राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए हज हाउस का निर्माण करवा रहे हैं। जहां हज हाउस बनाया जा रहा है वहां मुसलमान नहीं रहते हैं।

विश्व हिंदू परिषद ने भी हज हाउस बनाने का विरोध किया है और कहा है कि वहां पर अगर हज हाउस बनाया गया तो उस क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं के लिए खतरनाक होगा और वहां शाहीन बाग जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार मुसलमानों के वोट बटोरने के लिए करदाताओं के खून पसीने के एक अरब की धनराशि को मिट्टी में मिला रही है।

अवधनामा (5 अगस्त) के अनुसार ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक पत्र लिखकर यह मांग की है कि द्वारका में हज हाउस के निर्माण के लिए भूमि के अलॉटमेंट को रद्द किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां पर कश्मीर जैसे हालात पैदा होंगे और हिंदुओं को उस क्षेत्र से भागना पड़ेगा। सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हासमी ने इस पत्र का विरोध करते हुए कहा है कि यह पत्र साम्प्रदायिकता भड़काता है और सरकार को इस फेडरेशन के पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। समाचारपत्र का कहना है कि द्वारका क्षेत्र के निवासियों के बीच हज हाउस के निर्माण को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया है। इस क्षेत्र के 100 से अधिक निवासियों ने एक बयान जारी करके द्वारका में हज हाउस बनाने का समर्थन किया है और कहा है कि कुछ साम्प्रदायिक ताकतें जानबूझकर हज हाउस की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ वातावरण बना रही हैं। उन्होंने दावा किया है कि जो संगठन हज हाउस बनाने का विरोध कर रहे हैं उनका इस क्षेत्र में कोई जनाधार नहीं है।

विश्व

उर्दू मीडिया में तालिबान के इस्लामिक शासन का स्वागत

अफगानिस्तान में अप्रत्याशित रूप से तालिबान ने जिस ढंग से संपूर्ण देश पर कब्जा कर लिया उसका लगभग सभी उर्दू समाचारपत्रों ने स्वागत किया है और उसे इस्लाम की फतह की संज्ञा दी है। इन समाचारपत्रों ने इस बात पर भी खुशी प्रकट की है कि अफगानिस्तान में इस्लामिक शरिया का शासन स्थापित हो रहा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (16 अगस्त) का शीर्षक है– "इस्लामिक इतिहास की महान विजय, तालिबान काबुल में दाखिल, अशरफ गनी फरार, 20 साल के बाद सत्ता में वापसी, देश भर में आम माफी का ऐलान, काबुल में जगह–जगह जोरदार नारों के साथ स्वागत।"

सालार (16 अगस्त) का शीर्षक है– "अफगानिस्तान में इस्लाम की शानदार फतह, शरिया हुकूमत की स्थापना से जनता में खुशी की लहर, इस्लामिक जगत में तालिबान की जीत से प्रसन्नता।"

औरंगाबाद टाइम्स (16 अगस्त) ने शीर्षक दिया है–"इस्लामिक हुकूमत की स्थापना से इस्लामिक जगत में खुशी की लहर।"

रोजनामा सहारा (16 अगस्त) का शीर्षक है– "तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज।"

हमारा समाज (16 अगस्त) का शीर्षक है– "अफगानिस्तान में इस्लाम की फतह, अमेरिका को दुम दबाकर भागना पड़ा।"

अवधनामा (16 अगस्त) का शीर्षक है–"तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज, इमारत–ए–इस्लामिया की स्थापना।"

इन शीर्षकों से उर्दू समाचारपत्रों के रूख का सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है।

लखनऊ से प्रकाशित साप्ताहिक **जदीद मरकज** (22 अगस्त) ने इस समाचार को प्रमुख रूप से छापते हुए कहा है– "20 वर्ष बाद तालिबान की वापसी, अफगानिस्तान से भागा अमेरिका।" समाचार में कहा गया है कि तालिबान के काम करने के तरीकों से भले ही हम इत्तेफाक न रखें मगर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि तालिबान ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका को अपने मुल्क से भगा दिया है और कोई हिंसा किए बगैर काबुल पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका के पिट्ठू अशरफ गनी ने सरकारी खजाने के साथ कजाकिस्तान में शरण लेने का प्रयास किया था। जब उन्हें वहां उतरने की अनुमति नहीं दी गई तो वे भागकर कतर चले गए। समाचारपत्र ने लिखा है कि पूरे मुल्क पर तालिबान का कब्जा होने के बाद भी कहीं से हिंसा की कोई खबर नहीं आई। चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान वगैरह ने तालिबान के साथ जो रवैया जाहिर किया है वह भारत के लिए बड़ी फिक्र की बात है। तालिबान का आना भारत और खासकर कश्मीर में दहशतगर्दी में इजाफा करेगा।

मुंबई उर्दू न्यूज (17 अगस्त) के अनुसार शेख उल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि काबुल में तालिबान के शांतिपूर्ण ढंग से दाखिला, आम माफी और शांति की गारंटी ने पैगम्बर द्वारा मक्का की विजय की घटना की याद ताजा कर दी है। अफगानिस्तान की घटना ने यह सिद्ध कर दिया है कि दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति भी ईमान और इस्लाम के सामने नहीं टिक सकती। अब इस्लामिक जगत को इस चमत्कार से शिक्षा लेनी चाहिए। जमीयत उलेमा–ए–इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हम तालिबान का पूरा समर्थन करते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया था और हमने तालिबान का साथ दिया था क्योंकि वे मजलूम थे। तालिबान की जीत पर प्रसन्न होना उन लोगों के लिए जरूरी है जो कि कुरान और शरिया पर विश्वास रखते हैं। अगर किसी को इस्लाम और तालिबान की जीत से कोई परेशानी है तो हमें उससे कोई लेना–देना नहीं। जमात–ए–इस्लामी, पाकिस्तान के प्रमुख मौलाना सिराजुल हक ने कहा है कि जिस प्रशासन पर जनता को विश्वास न हो उसे दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत हथियारों के बल पर नहीं बचा सकती। उन्होंने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान को शांति, न्याय और इस्लामिक शरिया का देश बनाएंगे और उसे एक इस्लामिक देश के रूप में दुनिया के सामने उदाहरण स्वरूप पेश करेंगे।

दारूल उलूम ऑनलाइन, अमेरिका के प्रमुख डॉ. यासिर नदीम अल–वाजिदी ने अफगानिस्तान में दौलत–ए–इस्लामिया की स्थापना पर हार्दिक बधाई दी है और कहा है कि अल्लाह ने आपको एक और मौका दिया है कि आप इस्लाम और कुरान पर आधारित न्याय और शांति का इस्लामिक शासन उदाहरण के रूप में दुनिया के सामने पेश करेंगे। काबुल में आपके दाखिले से पैगम्बर–ए–इस्लाम के मदीना से मक्का की जीत की याद ताजा हो गई है।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नुमानी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए तालिबान को बधाई दी है और इस बात का खंडन किया है कि तालिबान जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान नबी के पद्–चिन्हों पर चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद रिहान खान ने भी तालिबान द्वारा अमेरिका को मुहतोड़ शिकस्त देने के लिए बधाई देते हुए कहा है कि तालिबान ने यह कदम अफगानिस्तान में शांति स्थापना के लिए उठाया है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि यह अफगानिस्तान का अपना मामला है। अब तालिबान ने अमेरिकी गुलामी से मुक्ति प्राप्त की है और इस्लाम का

सिर बुलंद किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि तालिबान अपने देश का प्रबंधन इस्लामिक सिद्धांतों के अनुसार करेंगे।

नवभारत टाइम्स (18 अगस्त) में प्रकाशित समाचार में यह दावा किया गया है कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है। पुलिस में दर्ज मुकदमे के अनुसार बर्क ने तालिबान का पक्ष लेते हुए कहा है कि भारत जब अंग्रेजों के कब्जे में था तब देश ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अब तालिबान भी अपने देश को आजाद कराकर उसे अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। उन्होंने तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से की है।

सियासत (17 अगस्त) के अनुसार तालिबान ने राजधानी काबुल और राष्ट्रपति भवन पर नियंत्रण के बाद यह स्पष्ट किया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विश्व बिरादरी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। तालिबान के प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने एक इंटरव्यू में कहा है कि तालिबान किसी अन्य देश के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और वे चाहते हैं कि कोई दूसरा देश भी हमारे मामले में हस्तक्षेप न करे। नईम ने अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अफगानिस्तान में गत 20 वर्षों से जो जंग चल रही थी वह समाप्त हो चुकी है। अब नई सरकार बनाने की तैयारी है और नए प्रशासन की रूप–रेखा शीघ्र ही स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि अफगानिस्तान की नई सरकार कुरान और शरिया पर आधारित होगी। शरिया के अनुसार अल्पसंख्यकों और महिलाओं को उनके जायज हक दिए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि तालिबान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और हम सभी अफगान नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसी भी शक्ति को अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल किसी अन्य देश के खिलाफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमें आशा है कि विदेशी ताकतें अफगानिस्तान में अपने विफल प्रयोगों को दोबारा दोहराने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हमें पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के फरार होने की उम्मीद नहीं थी। किसी भी दूतावास को निशाना नहीं बनाया जाएगा। सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अफगान तालिबान की राजनीतिक शाखा के प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने कहा है कि अल्लाह ताला की मदद से तालिबान को ऐसी विजय मिली है जिसकी हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। लेकिन मानसिक गुलामी की जंजीरों को तोड़ना भी बेहद जरूरी है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में सभी विचारधारा की सरकार बने।

इंकलाब (13 अगस्त) के अनुसार अमेरिकी विशेषज्ञों ने यह आशा व्यक्त की थी कि तीन महीने तक अफगान सेना तालिबान से टक्कर लेने की स्थिति में है। ब्रिटिश समाचारपत्रों ने इस अवधि को एक से दो महीने करार दिया था।

अखबार–ए–मशरिक (17 अगस्त) के अनुसार अफगानिस्तान में जिस तरह से अचानक तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा किया है उससे संपूर्ण विश्व शक्तियां हैरान हो गई हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि जिन तीन लाख अफगान फौजियों को खरबों डॉलर खर्च करके गत 20 वर्षों में हमने प्रशिक्षण दिया था और उन्हें अति आधुनिक अस्त्र–शस्त्रों से लैस किया था वे एक दिन भी 70 हजार अफगान तालिबान के सामने टिक नहीं सके। हमें अफगान सेना की इतनी बड़ी विफलता की आशा नहीं थी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन पर हमला करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में अमेरिका को जिस तरह से

मुंह की खानी पड़ी है उसको देखते हुए बाइडेन को फौरन त्यागपत्र दे देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अगर वे राष्ट्रपति होते तो तालिबान इस तरह से कभी अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं करता। दूसरी ओर बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि आज अफगानिस्तान में जो स्थिति है उसके लिए ट्रम्प ही पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। क्योंकि तालिबान और अमेरिका के बीच वार्ता की शुरुआत फरवरी 2020 में उन्हीं के शासनकाल में हुई थी।

गत एक वर्ष से तालिबान चीन, रूस एवं पाकिस्तान के जिस तरह से चक्कर काट रहे थे उसकी पृष्ठभूमि अब उभर कर सामने आई है।

सहाफत (17 अगस्त) के अनुसार एक ओर तो अमेरिका और उसके सहयोगियों ने काबुल में अपने दूतावास बंद कर दिए हैं दूसरी ओर पाकिस्तान, चीन और रूस ने घोषणा की है कि वे अपने दूतावासों का कामकाज जारी रखेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि उसका इरादा काबुल में दूतावास को बंद करने का नहीं है।

सहाफत में ही प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार हालांकि तालिबान ने आम माफी की घोषणा कर दी है मगर काबुल में अफरातफरी का वातावरण है। काबुल में तालिबान जगह–जगह गोलियां चला रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरातफरी के कारण सात लोग मारे गए हैं। कई अफगान देश से फरार होने के चक्कर में अमेरिका के एक सैनिक जहाज के पहियों पर सवार हो गए थे जो कि विमान की उड़ान के दौरान भूमि पर गिर पड़े और मर गए।

अखबार–ए–मशरिक (17 अगस्त) के अनुसार काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान की फायरिंग से अनेक लोग मारे गए हैं।

औरंगाबाद टाइम्स (17 अगस्त) ने अपने मुख्य पृष्ठ पर एक समाचार प्रकाशित किया है, जिसमें यह आशा व्यक्त की गई है कि तालिबान की सरकार को चीन, रूस, तुर्की,

ईरान और पाकिस्तान तुरंत मान्यता दे देंगे। तालिबान की राजनीतिक शाखा के प्रमुख मौलाना अब्दुल गनी बरादर ने अपने ऑनलाइन वीडियों में कहा है कि अब अफगानिस्तान का नाम 'इमारत–ए–इस्लामिया, अफगानिस्तान' होगा और हम इस्लामिक शरिया और कुरान के अनुसार अपना शासन चलाएंगे।

सियासत (17 अगस्त) के अनुसार काबुल में रूस के दूतावास ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी चार कारें और एक हेलीकॉप्टर को नकदी से भरकर अफगानिस्तान से फरार हो गए हैं। कहा जाता है कि वे ताजिकिस्तान पहुंच गए हैं। अशरफ गनी ने दावा किया है कि देश में रक्तपात को रोकने केलिए उन्होंने काबुल से निकल जाना ही उचित समझा है।

इंकलाब (17 अगस्त) के अनुसार विश्व के 64 देशों ने एक बयान जारी करके तालिबान से यह अनुरोध किया है कि वे विदेशियों और अफगानों को अफगानिस्तान से सुरक्षित चले जाने की सुविधा दें। सड़कें, हवाई अड्डे और सीमाएं खुली रखी जाएं। अल्बानिया ने कहा है कि अमेरिका पर भरोसा करने वालों को अफगानिस्तान की हालत से शिक्षा लेनी चाहिए।

अवधनामा (17 अगस्त) के अनुसार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान के तालिबान को तभी मान्यता देगा जब वह अपनी जनता के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा करे और आतंकवादियों को अपने देश से दूर रखे। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान अफगानिस्तान में आतंकवादियों को शरण देना बंद नहीं करेंगे तो उन्हें किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय सहायता नहीं दी जाएगी और उन पर विभिन्न तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी। जब उनसे पूछा गया कि क्या अमेरिका अफगानिस्तान में विफल रहा है तो उन्होंने कहा कि हमने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है।

इसी समाचारपत्र में प्रकाशित एक अन्य समाचार के अनुसार ईरान ने कहा है कि वह अफगान जनता का समर्थन जारी रखेगा और वह चाहता है कि वहां की समस्याओं को शांतिपूर्ण और बातचीत से हल किया जाए। ईरान अफगानिस्तान में विभिन्न गुटों के बीच समझौता करवाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा है कि वे अफगानिस्तान में ही रहेंगे और कहीं बाहर नहीं जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद खतीबजादेह ने कहा है कि अफगानिस्तान में ईरान के पांच कार्यालय थे, जिनमें 4 को बंद किया जा चुका है और सिर्फ काबुल में ही हमारा दूतावास काम कर रहा है। हालांकि काबुल में भी हम अपने कर्मचारियों को कम कर चुके हैं।

समाचार एजेंसी 'आईएएनएस' के अनुसार अफगानिस्तान के युद्धग्रस्त क्षेत्रों से एक लाख से अधिक लोग भागकर काबुल के पार्कों में डेरे डाले हुए थे। दिल्ली में रहने वाले एक अफगान ने यह दावा किया है कि इन शरणार्थियों की हजारों महिलाएं रहस्यमय ढंग से गायब हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उनका अपहरण तालिबान ने किया है।

इत्तेमाद (17 अगस्त) के अनुसार चीन ने घोषणा की है कि वह तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की इच्छा रखता है। चीन का कहना है कि अफगानिस्तान की जनता को अपने भाग्य का निर्णय करने का पूरा अधिकार है। चीन अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध और सहयोग में और भी वृद्धि करना चाहता है। जबकि रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम अफगानिस्तान की स्थिति पर नजर रख रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने काबुल में अपना दूतावास खाली कर दिया है और अपने स्टाफ को वापस बुला लिया है।

हमारा समाज (17 अगस्त) के अनुसार तालिबान ने यह घोषणा की है कि

अफगानिस्तान का शासन इस्लामिक शरा के अनुसार चलाया जाएगा। तालिबान ने सभी मुजाहिदीन को यह कड़े निर्देश दिए हैं कि वे बिना अनुमति के किसी भी व्यक्ति के मकान में दाखिल न हों। क्योंकि हम वहां की जनता को सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं। बीबीसी ने घोषणा की है कि तालिबान नागरिकों के घरों में दाखिल होकर वहां रखे हुए अस्त्र–शस्त्रों को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं। तालिबान का दावा है कि अब नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेवारी उनकी है। इसलिए अब इन अस्त्र–शस्त्रों की कोई जरूरत नहीं है। यह भी समाचार मिला है कि अफगानिस्तान की जेलों में अमेरिका ने जिन हजारों आतंकवादियों को बंद कर रखा था उन्हें रिहा कर दिया गया है। रिहा किए गए लोगों में तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान के उपप्रमुख मौलवी फकीर मोहम्मद और पाकिस्तान द्वारा वांछित आतंकवादी शामिल हैं।

समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि पंजशीर घाटी पर अभी तक तालिबान का कब्जा नहीं है। इस घाटी के प्रमुख लड़ाकू नेता अहमद मसूद ने कहा है कि अगर तालिबान बंदूक के जोर पर उन पर अपनी विचारधारा नहीं लादेंगे तो वे उनसे वार्ता करने के लिए तैयार हैं। उनके पिता अहमद शाह मसूद को अफगानिस्तान में तालिबान का सबसे बड़ा विरोधी माना जाता था।

सहाफत (17 अगस्त) ने अपने संपादकीय में अफगानिस्तान में इस्लामिक इमारत (इस्लामिक शासन) का स्वागत किया है। अफगानिस्तान की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 36 लाख है और इसमें 80 प्रतिशत सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि 19 प्रतिशत शिया हैं। इनमें से 42 प्रतिशत पश्तून, 29 प्रतिशत ताजिक, 9 प्रतिशत हजारा और 9 प्रतिशत उज्बेक कबीलों से संबंधित हैं। सहाफत ने लिखा है कि हम बार–बार भारत सरकार को इस बात की चेतावनी देते रहे हैं कि वह अफगानिस्तान में अरबों डॉलर का पूंजी निवेश न करे। मगर किसी ने हमारी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। समाचारपत्र ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है

कि एक ओर तो चीन के साथ तालिबान के दोस्ताना संबंध होने का दावा किया जा रहा है। जबकि चीन लाखों उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस्लाम का दंभ भरने वाले तालिबान इन्हीं चीनी मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर रहे हैं।

सियासत (15 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम से भारत के लिए खतरा बढ़ गया है। तालिबान ने भारत को चेतावनी दी है कि वह अफगानिस्तान में किसी तरह की सैनिक भूमिका निभाने से दूर रहे। भारत ने हमेशा अफगानिस्तान के नवनिर्माण में एक जिम्मेवार पड़ोसी की भूमिका निभाई है। वर्तमान हालात में हिंदुस्तान को ज्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व के लिए दुनिया के सभी देशों को आगे आना चाहिए।

सियासत ने 16 अगस्त के विशेष संपादकीय में अफगानिस्तान से बढ़ते हुए खतरे के बारे में भारत को चेतावनी दी है और यह आशंका व्यक्त की है कि लश्कर–ए–तैयबा, जैश–ए–मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन देश में और सक्रिय होंगे। इस बात की संभावना है कि अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद वहां के प्रशासन में पाकिस्तान के प्रभाव में वृद्धि हुई है, जिसके कारण भारतीय हितों को चोट पहुंचेगी। अब अफगानिस्तान में भारत की भूमिका काफी कम हो जाएगी। अब अफगानिस्तान की तिजारत पाकिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों से होगी। ऐसी स्थिति में भारत के सामने तीन विकल्प हैं। पहला तो यह कि भारत काबुल में स्थापित होने वाली सरकार का समर्थन करता रहे और उसे सहायता जारी रखे। दूसरा, भारत अफगानिस्तान में किसी तरह का हस्तक्षेप न करे। तीसरा रास्ता यह है कि भारत तालिबान से संपर्क स्थापित करने का प्रयास न करे। हालांकि तालिबान की ओर से इसका सकारात्मक उत्तर मिलने की संभावना

नहीं है। क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के चंगुल में है।

अवधनामा (17 अगस्त) ने कहा है कि 2001 में अफगानिस्तान पर अमेरिका और उसके 29 सहयोगियों ने हमला बोला था। उस समय अफगानिस्तान में तालिबान की ही सरकार थी। अमेरिका की मांग थी कि तालिबान अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को उसके हवाले कर दे। मगर तालिबान सरकार ने इसे मानने से इंकार कर दिया। अब 20 साल के बाद अमेरिका को अफगानिस्तान से बोरिया–बिस्तर बांधकर बाहर निकलना पड़ा है। एक ओर तो अमेरिका अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार को सहायता का आश्वासन देता रहा। दूसरी ओर वह तालिबान से गुप्त बात भी करता रहा और अचानक उसने अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार को तालिबान की दया पर छोड़ दिया। अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान को खाली करने के तुरंत बाद अशरफ गनी की सरकार ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए और पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया। तालिबान के पास इस्लाम की दौलत थी, जिसके कारण अमेरिका जैसी सुपरपावर भी उसका कुछ न बिगाड़ सकी और रूस को भी उन्होंने मार–मारकर भगा दिया। भारत को अफगानिस्तान के हालात पर बारिकी से नजर रखनी चाहिए।

इत्तेमाद (17 अगस्त) ने इस बात पर जोर दिया है कि तालिबान को अफगानिस्तान में आदर्श इस्लामिक हुकूमत कायम करनी चाहिए और वहां की जनता को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि तालिबान शरा और कुरान पर चलते हुए जनता को शांति और स्थिरता प्रदान करे।

हमारा समाज (17 अगस्त) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अफगानिस्तान में जो उथल–पुथल हो रही है उससे वहां पर भारत के लिए खतरा बढ़ गया है इसलिए भारत को हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए।

मुंबई उर्दू न्यूज (17 अगस्त) ने कहा है कि तालिबान ने इससे पूर्व 1996 से लेकर 2001 तक जब अफगानिस्तान पर शासन किया था तो उस समय उन्होंने सख्त शरई कानून लागू किए थे। मगर अब तालिबान खुद को एक हद तक लिबरल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। शायद उनकी नीति में जो परिवर्तन हुआ है वह सऊदी अरब में हुए परिवर्तन का प्रभाव हो सकता है। यही कारण है कि तालिबान के प्रवक्ता ने यह आशा व्यक्त की है कि वे अफगानिस्तान में शांति और राजनीतिक स्थिरता के लिए सभी गुटों से सहयोग लेंगे और किसी की व्यक्तिगत संपत्ति पर जबरन कब्जा नहीं करेंगे और महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जाएगा। यही कारण है कि उन्होंने यह भी कहा है कि जो देश अफगानिस्तान में नवनिर्माण के कार्य में लगे हुए हैं उनके कार्य में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। समाचारपत्र ने मोदी सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह बदले हुए हालात में तालिबान के साथ संपर्क स्थापित करे।

मलेशिया के प्रधानमंत्री का त्यागपत्र

इत्तेमाद (17 अगस्त) के अनुसार मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन और उनकी सरकार ने अपना त्यागपत्र मलेशिया के शासक को पेश कर दिया है। वे 17 महीने सत्ता में रहे। उन्हें इसलिए अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा क्योंकि उनके सहयोगी दलों ने उनकी सरकार का समर्थन करने से इंकार कर दिया था। मलेशिया के एक मंत्री मोहम्मद रेडजुआन युसूफ ने इस बात की पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने अपने पद से त्यागपत्र दे

दिया है मगर अभी तक मलेशिया के शासक ने किसी अन्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया है। न ही नए चुनाव करवाने की ही घोषणा की है। इसका कारण यह है कि देश कोरोना की महामारी और आर्थिक बदहाली से जूझ रहा है। सिंगापुर इंस्टिट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के विशेषज्ञ ओह ई सन का कहना है कि यासीन के त्यागपत्र देने से मलेशिया की संसद के विभिन्न गुटों के बीच राजनीतिक गठबंधनों का नया दौर शुरू हो गया है। अभी यह कहना कठिन है कि देश की राजनीति कौन सी करवट लेगी। मलेशिया के संविधान के अनुसार वहां का संवैधानिक शासक उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है,

जिसे संसद में बहुमत प्राप्त हो। पिछले वर्ष मार्च महीने में तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त होने के कारण अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था।

नवाज शरीफ की वीजा अवधि बढ़ाने से ब्रिटेन का इंकार

सियासत (11 अगस्त) के अनुसार ब्रिटेन के गृहमंत्रालय ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग (नवाज) के नेता नवाज शरीफ के वीजा की अवधि में वृद्धि करने से इंकार कर दिया है। इसके साथ ही नवाज शरीफ के लिए जबर्दस्त संकट उत्पन्न हो गया है। क्योंकि अगर वे पाकिस्तान वापस आते हैं तो वहां की सरकार उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद कर देगी। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इस बात की पुष्टि की है कि ब्रिटेन के गृहमंत्रालय ने नवाज शरीफ के वीजा की अवधि को बढ़ाने से इंकार कर दिया है। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी का आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने से बचने के लिए नवाज शरीफ ने फर्जी डॉक्टरी रिपोर्टों का सहारा लिया और इलाज कराने के बहाने वे ब्रिटेन चले गए थे। हालांकि वे बीमार नहीं हैं। सिर्फ वे जेल जाने से बचना चाहते हैं। पाकिस्तान सरकार ने ब्रिटिश सरकार से मांग की है कि वह भ्रष्टाचारी नवाज शरीफ को अपने

देश में पनाह न दे। उन्हें फौरन पाकिस्तान भेजा जाए ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अक्टूबर 2019 में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 8 हफ्तों के लिए जमानत दी थी। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें मानवीय आधार पर विदेश जाने की अनुमति दी

थी। तब से वे लंदन में रह रहे हैं। नवाज शरीफ को इस बात का भय है कि अगर वे स्वदेश लौटे तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वकीलों की सहायता से ब्रिटिश गृहमंत्रालय द्वारा वीजा अवधि में वृद्धि न करने के फैसले को ब्रिटिश इमिग्रेशन ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है। जब तक ट्रिब्यूनल उनकी याचिका के बारे में कोई फैसला नहीं करती तब तक वे ब्रिटेन में कानूनी तौर पर रह सकते हैं। ■

शिंजियांग क्षेत्र में रूस और चीन का संयुक्त सैनिक अभ्यास

हमारा समाज (14 अगस्त) के अनुसार उत्तर–पश्चिम चीन में इन दिनों व्यापक पैमाने पर चीन और रूस की सेनाएं संयुक्त सैनिक अभ्यास कर रही हैं। इनमें स्थल सेना के साथ–साथ वायु सेना के लड़ाकू विमान भी भाग ले रहे हैं। इन दोनों देशों के बीच सैनिक तालमेल बढ़ाने का प्रयास पड़ोसी देश अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए किया गया है। ये संयुक्त अभ्यास निंगशिया क्षेत्र में हो रहे हैं जो कि चीन के शिंजियांग प्रदेश के पूर्व में स्थित है। शिजियांग की सीमा अफगानिस्तान से मिलती हैं। चीन को इस बात का भय है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के निष्कासन के बाद इस्लामिक आतंकवाद इस क्षेत्र में पनप सकता है। यह वही क्षेत्र है जहां चीन ने दस लाख से अधिक उइगर मुसलमानों को नजरबंदी शिविरों में रखा हुआ है। चीन का दावा है कि उन्हें आतंकवाद और अतिवाद के अभियान के दौरान गिरफ्तार किया गया है। जबकि पश्चिमी मीडिया का यह कहना है कि चीन जानबूझकर अपने क्षेत्र से मुसलमानों का नामोंनिशान मिटाना चाहता है और वह मुसलमानों की नई पीढ़ी को इस्लाम से दूर करने की नीति पर चल रहा है। चीन की सरकारी संवाद समिति के अनुसार इन सैनिक अभ्यासों का लक्ष्य चीन और रूस के सैनिकों के बीच आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने के तंत्र को सुदृढ़ बनाना है। सरकारी संवाद समिति ने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र में जो राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है उसको देखते हुए यह जरूरी है कि दोनों देश अपनी नई सैनिक नीति का

पुनर्निर्धारण करें। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन अभ्यासों का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैनिक संबंधों को बढ़ाना और दोस्ती की भावना को पैदा करना है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि चीन और रूस दोनों मिलकर इस क्षेत्र में पनपने वाले आतंकवाद का संयुक्त रूप से मुकाबला करेंगे। हाल ही में रूस ने दक्षिणी चीन सागर पर चीनी दावे का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में इस संबंध में चीनी और अमेरिकी प्रतिनिधियों के बीच जबर्दस्त झड़पें हुई थीं। कई दशक से दक्षिणी चीन सागर पर चीन, ताइवान और आशियान देश ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस और वियतनाम अपना दावा करते रहे हैं। चीन ने हाल ही में इस विवादित क्षेत्र में कई द्वीपों पर कब्जा करके वहां पर अपने मिसाइल के अड्डे स्थापित कर दिए हैं। इससे अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ गया है। चीन ने दावा किया है कि अमेरिका जानबूझकर इस क्षेत्र में तनाव बढ़ा रहा है।

महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति तोड़ने वाला गिरफ्तार

इंकलाब (18 अगस्त) के अनुसार लाहौर के शाही किले में महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस घटना की निंदा की है और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन तहरीक–ए–लब्बैक के एक कार्यकर्ता रिजवान अहमद को लाहौर के शाही किले में स्थापित महाराजा रंजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ते हुए दिखाया गया था। लाहौर के वरिष्ठ पुलिस आयुक्त गुलाम महमूद डोगर ने प्रधानमंत्री से मिले निर्देश के बाद आरोपी रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है और कहा है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सहायक डॉ. शहबाज गुल ने एक ट्विट में कहा है कि जिस व्यक्ति ने यह हरकत की है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व लाहौर के शाही किले के बाहर महाराजा रंजीत सिंह की घोड़े पर सवार मूर्ति को स्थापित किया गया था। पाकिस्तान का शासक वर्ग सिखों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहन दे रहा है।

हाल ही में पाकिस्तान के कई गुरुद्वारों की मरम्मत भी की गई है और विदेशों में रहने वाले सिखों को जत्थों के रूप में पाकिस्तान लाकर इन गुरुद्वारों का दर्शन करवाया जाता है। इसी संबंध में महाराजा रंजीत सिंह की इस मूर्ति की स्थापना की गई थी और लाहौर के शाही किले में सिख आर्ट गैलरी भी बनाई गई थी। इससे पूर्व भी 2019 में चार लोगों ने इस मूर्ति पर हमला करके उसको तोड़ दिया था। पाकिस्तानियों का एक वर्ग महाराजा रंजीत सिंह को इस्लाम और मुसलमानों का दुश्मन मानता है और उनकी ओर से यह आरोप लगाया जाता है कि महाराजा ने अपने शासनकाल मे कई मस्जिदों को गुरुद्वारों में बदल दिया था। इनमें लाहौर स्थित शहीदगंज की मस्जिद उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त मुस्लिम काल के अनेक मकबरों को सिख राज में क्षति पहुंचाई गई थी।

क्या संकट का समाधान कर पाएंगे ईरान के नए राष्ट्रपति?

इंकलाब (7 अगस्त) के अनुसार इब्राहिम रईसी ने ईरान के आठवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद देश को मजबूत बनाने और विश्व शक्तियों से वार्ता शुरू करने पर बल दिया है। उधर अमेरिका ने नए राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे परमाणु संधि के बारे में पुनः बातचीत शुरू करें। अमेरिकी प्रवक्ता ने यह आशा व्यक्त की है कि ईरान इस स्थिति का लाभ उठाकर राजनयिक स्तर पर इस विवाद को हल करने के लिए आगे बढ़ेगा। बातचीत का यह सिलसिला अनिश्चितकाल तक आगे नहीं चल सकता। शपथ लेने के बाद ईरानी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करवाने के लिए वे राजनयिक योजना का समर्थन करेंगे। परमाणु संधि के मामले में अमेरिका के संबंध ईरान के साथ काफी तनावपूर्ण रहे हैं। इब्राहिम रईसी ने शपथ समारोह के बाद कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हुए हैं वह समाप्त होने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि दबाव और प्रतिबंधों की राजनीति ईरान को उसके अधिकार से पीछे नहीं हटा पाएगी।

इंकलाब (7 अगस्त) के अनुसार ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने के बाद बताया कि ईरान का यह प्रयास होगा कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाए। संयुक्त अरब अमीरात इस क्षेत्र में ईरान का सच्चा दोस्त है। उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीन की पीड़ित जनता के समर्थक हैं और हर तरह के दबाव और प्रतिबंधों के बावजूद हम फिलिस्तीनी जनता की रक्षा में अपना धार्मिक और मानवीय कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और हमें आशा है कि विश्व के सभी मुसलमान और अरब देश इस संबंध में गंभीर कदम उठाएंगे ताकि यहूदियों की आक्रामकता को समाप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि

जहां तक यमन के भविष्य का सवाल है उसके बारे में निर्णय वहीं की जनता करेगी। इस क्षेत्र के सभी देशों को चाहिए कि वे यमनी जनता का समर्थन करें और उनके अधिकारों की रक्षा करें। उन्होंने आरोप लगाया कि यहूदी और ईसाई मुसलमानों को विभाजित करना चाहते हैं और उन्हें कमजोर करना चाहते हैं। इससे पूर्व ईरानी राष्ट्रपति ने अपने नए पद की शपथ ली और कहा कि वे देश की जनता के हितों के साथ किसी तरह का सौदा नहीं करेंगे और सभी मुस्लिम देशों के साथ संबंधों को सुधारेंगे।

इससे पूर्व ईरान के राष्ट्रपति ने बेलारूस की संसद के अध्यक्ष से भी मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के संबंधों में सुधार लाने के लिए एक संयुक्त आयोग स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विकास की बेशुमार संभावनाएं हैं जिनका उपयोग दोनों देशों की जनता की भलाई में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यह ख्याल था कि वह ईरान के विकास मार्ग को अवरूद्ध कर देगा। मगर उसकी यह उम्मीद पूरी नहीं हुई। ईरान अमेरिकी बाधाओं के बावजूद विकास के मार्ग पर अग्रसर है।

इत्तेमाद (7 अगस्त) ने अपने संपादकीय में ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के सत्ता संभालने का स्वागत किया है और कहा है कि उदारवादी हसन रूहानी के बाद कट्टरपंथी इब्राहिम रईसी ने अपना पद पुनः संभाल लिया है। उनके चुनाव की पुष्टि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खुमैनी द्वारा किए जाने के बाद उन्होंने देश के आठवें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। रईसी ने उस समय कार्यभार संभाला जब ईरान को विदेशी और आंतरिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है। देश में बढ़ती महंगाई, बिजली और पानी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक इजरायली टैंकर पर हमले का आरोप लगाकर अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल ने ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की धमकी दी है। हालांकि ईरान ने यह स्पष्ट किया है कि इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं है। ईरान इस समय इस शताब्दी में सबसे बड़े अकाल और सूखे का सामना कर रहा है। इसके कारण बिजली और पानी का संकट है और कोरोना महामारी भी तेजी से फैल रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण महंगाई आसमान छू रही है और ईरान के विभिन्न भागों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है कि नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। रईसी ने अपने चुनाव अभियान में कई वायदे किए थे, जिनमें आर्थिक स्थिति को सुधारना भी शामिल था। इसके लिए यह जरूरी है कि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वह पहले समाप्त हों। रईसी को विदेश नीति और प्रशासन का कोई अनुभव नहीं है। वे राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व तक देश के न्यायपालिका के प्रमुख थे। पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी के शासनकाल में मोहम्मद जवाद जरीफ विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रमुख थे। वे 20 वर्षों तक अमेरिका में रहे हैं इसलिए वे अमेरिका की राजनीति को भलीभांति समझते हैं। परमाणु समझौते को बहाल करने के बारे में वियना में दोनों पक्षों में वार्ता का सिलसिला जारी है। मगर दोनों पक्ष अपने–अपने स्टैंड पर अड़िग हैं। ईरान चाहता है कि अमेरिका पहले प्रतिबंध समाप्त करे। जबकि अमेरिका का कहना है कि ईरान पहले आश्वासनों को कार्यान्वित करे। अली बाकरी ईरान के नए विदेश मंत्री बनाए जा सकते हैं। वे रईसी के साथ काम कर चुके हैं। महमूद अहमदीनेजाद के शासनकाल में बाकरी विदेश नीति विभाग के प्रमुख सईद जलीली के सहायक रह चुके हैं। बाकरी ने तेहरान की इमाम सादिक यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की है।

इस विश्वविद्यालय में छात्रों को उनकी धार्मिक कट्टरता के आधार पर ही प्रवेश मिलता है। अमेरिका ने ईरान के तेल बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है और उसने यह धमकी दे रखी है कि जिसने ईरान से तेल खरीदा उस पर भी अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा। तेल से होने वाली आय और राष्ट्रीय उत्पादन में गिरावट के कारण ईरान आर्थिक संकट का शिकार है। 2017 से ईरान की यूरोपीय यूनियन देशों के साथ तिजारत में 85 प्रतिशत की गिरावट आई है। बलूमबर्ग के अनुसार ईरान के अतिवादी लोगों का इस बात पर दबाव है कि यूरोप के साथ व्यापारिक संबंधों को सुधारने की बजाय ईरान को चीन और रूस के साथ संबंध सुधारने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नए ईरानी राष्ट्रपति की नीति क्योंकि पश्चिम विरोधी है इसलिए वे आर्थिक क्षेत्र में कोई सुधार नहीं कर पाएंगे। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार ईरानी जनता का अपने नेतृत्व से मोहभंग हो रहा है। यही कारण है कि ईरान में हाल में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में आधे से ज्यादा मतदाताओं ने हिस्सा नहीं लिया था।

सियासत (11 अगस्त) ने इस बात पर जोर दिया है कि खाड़ी देशों और ईरान के बीच तनाव का वातावरण समाप्त होना चाहिए और इस्लामिक जगत को आपसी भेदभाव से उपर उठकर एकजुट होना चाहिए। समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि इस भेदभाव का मूल कारण अमेरिका का समर्थन और विरोध है। कुरान के आधार पर पूरे इस्लामिक जगत को कुफ्र, सर्क और कम्युनिज्म का एकजुट होकर मुकाबला करना चाहिए और दीन की जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए इस्लाम के प्रचार और यरुशलम की वापसी के लिए जिहाद का रास्ता अपनाना चाहिए।

समाचारपत्र ने कहा है कि अगर दो बड़े इस्लामिक देश सऊदी अरब और ईरान इस्लाम और मिल्लत इस्लामिया के हितों के कारण अपने मतभेदों को समाप्त कर दें तो इस्लामिक जगत एकजुट होकर हर तरह की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता रखता है। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ इजरायल के जो संबंध स्थापित हुए हैं उससे अरब राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इराक, कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के सैनिक अड्डे मौजूद हैं। सऊदी अरब और ईरान के बीच यमन को लेकर तनाव दिन–प्रतिदिन बढ़ रहा है। ■

संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच तेल सप्लाई समझौता खतरे में

इंकलाब (17 अगस्त) के अनुसार हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच तेल की सप्लाई के संबंध में जो गुप्त समझौता किया गया था वह रद्द कर दिया गया है। इससे दोनों देशों के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। संवाद समिति एपी की रिपोर्ट के अनुसार अबुधाबी और इजरायल ने इजरायली बंदरगाह 'इलात' द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के तेल को पश्चिमी देशों में भेजने के बारे में एक समझौता किया था। यह समझौता पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रयास से दोनों देशों के बीच संबंधों के सुधार के सिलसिले में किया गया था। यह समझौता यूरेसियन पाइपलाइन कंपनी और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुआ था जो कंपनी इजरायल की है और इजरायली–अमीराती एमइडी और आरइडी लैंड ब्रिड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। मगर हाल ही में इजरायल में जो प्रशासनिक परिवर्तन

हुआ है उसके बाद इजरायल ने इस समझौते पर पुनर्विचार करना शुरू किया था। उनका कहना था कि इस समझौते के कारण इजरायल के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नई

सरकार के इस कदम ने इस परियोजना के पूंजी निवेशकों को रूष्ट कर दिया और इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के आपसी संबंधों के बीच भी कटुता उत्पन्न हो गई।

इजरायल के कुछ पर्यावरण संरक्षक संगठनों ने इजरायल की सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि इस परियोजना के तहत तेल की सप्लाई पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस पर इजरायल के पर्यावरण मंत्री ने अदालत को यह आश्वासन दिया है कि इस समझौते को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया जाएगा। इजरायल के इस फैसले की संयुक्त अरब अमीरात में तीव्र प्रतिक्रिया हुई है और संयुक्त अरब अमीरात सरकार का कहना है कि इस समझौते को समाप्त करना राजनयिक संधि के खिलाफ है और इससे दोनों देशों के संबंधों को क्षति पहुंचेगी। इससे दोनों देशों के बीच हुए द्विपक्षीय संबंधों को भी झटका लगा है। इजरायली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात से जनवरी 2020 से लेकर जून के बीच दोनों देशों के बीच 45 करोड़ 70 लाख डॉलर का व्यापार हुआ था जबकि संयुक्त अरब अमीरात को 25 करोड़ 50 लाख डॉलर का माल भेजा गया था। जेबल अली बंदरगाह के आकड़ों के अनुसार सितंबर 2020 से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच 27 करोड़ 20 लाख डॉलर का कारोबार हुआ था।

सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग के चार आरोपियों को 24 वर्ष की सजा

अखबार–ए–मशरिक (15 अगस्त) के अनुसार सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग के चार आरोपियों को 24 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। सजा पूरी होने के बाद इन चारों आरोपियों को देश से निष्कासित कर दिया जाएगा। सऊदी न्याय विभाग के प्रवक्ता के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े केस में चार आरोपियों से जांच पड़ताल के बाद इनके कब्जे से दस करोड़ 40 लाख रियाल की रकम बरामद की गई थी। आरोपियों में एक व्यक्ति सऊदी अरब का नागरिक है जबकि अन्य तीन विदेशी हैं। ये लोग विदेशी बैंकों के माध्यम से अवैध रूप से सऊदी करेंसी को विदेशों में भेज रहे थे और उन्हें हर महीने 30 हजार रियाल की रकम रिश्वत के रूप में अदा की जाती थी। अदालत ने इन चारों आरोपियों को 24 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। कैद पूरी होने के बाद तीनों विदेशी नागरिकों को सऊदी अरब से निष्कासित कर दिया जाएगा। जबकि सऊदी नागरिक को सजा पूरी होने के बाद भी जेल से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। सरकारी बयान के अनुसार आरोपियों की ओर से 25 लाख रियाल की रकम को एक कंटेनर में छुपाकर विदेश भेजा गया था।

सऊदी अरब में विदेशियों को संपत्ति खरीदने की अनुमति

सियासत (16 अगस्त) के अनुसार सऊदी सरकार ने देश में कानूनी तौर पर रहने वाले विदेशियों को सऊदी अरब में संपत्ति खरीदने की अनुमति प्रदान कर दी है। सऊदी गजट के अनुसार ऐसे सभी गैर सऊदी नागरिक जो कि देश में कानूनी तौर पर रह रहे हैं अब एक–एक संपत्ति खरीद सकेंगे। मगर संपत्ति खरीदने के इच्छुक विदेशियों को तीन शर्तों का पालन करना होगा। उनमें पहली यह कि संपत्ति खरीदने के इच्छुक व्यक्ति के पास सऊदी अरब में रहने का वैध पहचान पत्र होना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे टाइटल डीड की एक कॉपी के साथ संपत्ति से संबंधित सभी जानकारी सरकार को उपलब्ध करवानी होगी। सऊदी अरब में उसकी कोई अन्य संपत्ति नहीं होनी चाहिए। गैर सऊदी नागरिकों को संपत्ति खरीदने से पूर्व सरकार से ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करनी होगी।

अल्जीरिया में आग से 65 लोग मरे

इत्तेमाद (14 अगस्त) के अनुसार अल्जीरिया के उत्तरी क्षेत्रों के वनों में भीषण आग लग गई है, जिसमें कम–से–कम 65 लोग मारे गए हैं। इनमें 28 सैनिक भी शामिल हैं। अल्जीरिया के राष्ट्रपति ने तीन दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अग्नि का सबसे ज्यादा प्रकोप तीन तटीय जिलों में हुआ है जहां पर अनेक नगर और कस्बे पूर्ण रूप से जल गए हैं। गत नौ दिनों से वन की इस भड़कती आग पर निरंतर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। इन दिनों तुर्की से लेकर ट्यूनीशिया के देशों में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी के कारण आग और भी भीषण रूप ले रही है। आग पर काबू पाने के लिए फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और चेक रिपब्लिक ने भी अग्निशामक दल भेजे हैं। आग यूनान के कई भागों को भी अपने लपेटे में ले चुकी है।

मुस्लिम लीग के छात्र प्रकोष्ठ का पुनर्गठन

इंकलाब (7 अगस्त) के अनुसार इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने अपने छात्र विंग मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का पुनर्गठन करने का फैसला किया है। इसका अध्यक्ष उन्नस अब्दुल्लाह, उपाध्यक्ष हाफिज महरूफ, शाहिद खान और अफजल युसूफ को चुना गया है। जबकि इसका महामंत्री फुरकान फारूक, सह सचिव अब्दुल्ला मुबिद रजा, सैयद सारिफ रजा, हाफिज ऐजाज, कोषाध्यक्ष अशरफुद्दीन और मीडिया सचिव खालिद महमूद को बनाया गया है। इस बैठक में यह निर्णय किया गया है कि राजधानी में मुस्लिम छात्रों को संगठित किया जाए ताकि मुसलमानों के साथ होने वाले अन्याय को रोका जा सके।

मायावती उतारेगी मुस्लिम उम्मीदवार

इंकलाब (11 अगस्त) के अनुसार उत्तर प्रदेश के आगामी विधान सभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की ओर से 100 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी है। इन उम्मीदवारों को उन क्षेत्रों से टिकट दिया जाएगा जहां पर विजय की कुंजी दलितों और मुसलमानों के हाथ में है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों, ठाकुरों और ओबोसी को भी टिकट देने का निर्णय किया गया है। इन दिनों क्योंकि ब्राह्मण वोटर भाजपा से नाराज चल रहे हैं इसलिए उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए राज्य में जगह–जगह ब्राह्मण सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। इस तरह के सम्मेलनों को प्रबुद्धजन सम्मेलन का नाम दिया गया है। इस तरह का एक सम्मेलन अयोध्या में आयोजित हो चुका है। मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेवारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मुनकाद अली, नौशाद अली और पूर्व मंत्री वसीम अराईं को सौंपी गई है।

मुस्लिम यूनिवर्सिटी गजट में मोदी का चित्र

सियासत (10 अगस्त) के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने विश्वविद्यालय की शताब्दी के संबंध में प्रकाशित होने वाले यूनिवर्सिटी गजट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के चित्रों की भरमार पर आपत्ति दर्ज की है। छात्र गत एक सप्ताह से इसके खिलाफ धरना दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि इस प्रकाशन में सर सैयद अहमद की उपेक्षा करके मोदी के चित्र को प्रकाशित करने पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस गजट में विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद के सिर्फ तीन चित्र हैं जबकि प्रधानमंत्री मोदी के सात चित्र प्रकाशित किए गए हैं। छात्र संघ ने विश्वविद्यालय के उपकुलपति को इस संदर्भ में एक ज्ञापन दिया है और आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए सर सैयद अहमद को नजरअंदाज करके प्रधानमंत्री मोदी को महत्व दे रहा है।

अहमदियों के खिलाफ अभियान

सियासत (13 अगस्त) के अनुसार आंध्र प्रदेश के वारंगल नगर में अहमदियों की ओर से थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, जिसमें मुस्लिम संगठनों पर यह आरोप लगाया गया है कि वे उन्हें परेशान कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अहमदियों को मस्जिदों में नमाज अदा करने से कट्टरवादी मुस्लिम रोक रहे हैं। इसके अतिरिक्त कब्रिस्तान में शवों को दफनाने में भी रूकावट डाली जा रही है। मजलिस तहफ्फुज खत्म–ए–नुबुव्वत की ओर से इस बात का भी प्रचार किया जा रहा है कि अहमदियों के निकाह मुस्लिम मौलाना न पढ़ाएं क्योंकि अहमदी गैर मुस्लिम हैं। देश के अनेक भागों में अहमदियों द्वारा यह शिकायत की जा रही है कि कट्टरवादी तत्वों द्वारा उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप किया जाता है।

इस्लामिक स्टेट का सदस्य जमानत पर रिहा

हमारा समाज (14 अगस्त) के अनुसार पिछले पांच वर्षों से जेल में बंद इकबाल अहमद कबीर अहमद को बंबई उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने आरोपी को यह आदेश दिया है कि जेल से रिहा होने के बाद वह अपने मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित रहेगा। महाराष्ट्र एटीएस ने अहमद को 5 वर्ष पूर्व यूएपीए एक्ट एवं विस्फोटक पदार्थ कानून की विभिन्न धाराओं के सिलसिले में गिरफ्तार किया था और उस पर यह आरोप लगाया गया था कि वह आईएसआईएस का सदस्य है और उसने उसके नेता अबु बकर अल बगदादी को अपना खलीफा माना है और इस संबंध में अरबी में एक हलफनामा भी लिखा हुआ है। मुंबई की न्यायालय में उसके मुकदमे की पैरवी जमीयत उलेमा की ओर से की गई। वकीलों ने कहा कि हालांकि आरोपी गत पांच वर्षों से जेल में है मगर अभी उसके खिलाफ किसी भी मुकदमें की शुरुआत नहीं हुई है। आरोपी को जमानत पर रिहा करने का विरोध सरकारी वकील अरूणा पाई ने किया। मगर न्यायालय ने उनकी आपत्ति को खारिज कर दिया।

RNI No. DELHIN/2017/72722

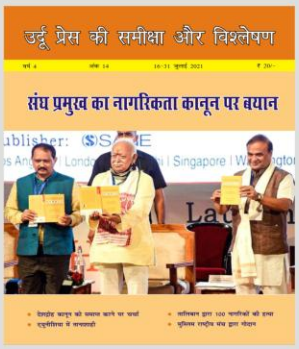

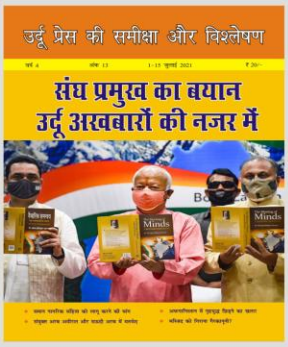

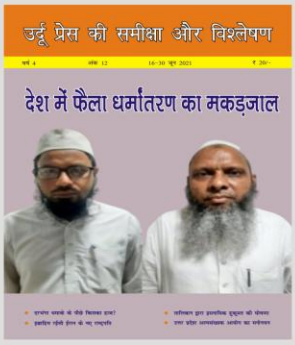

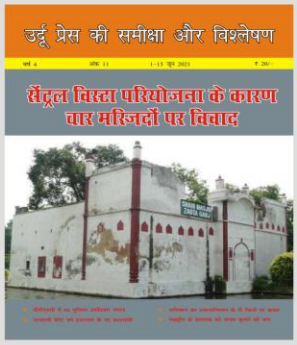

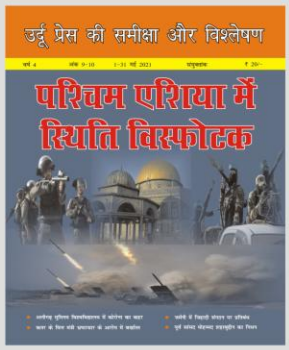

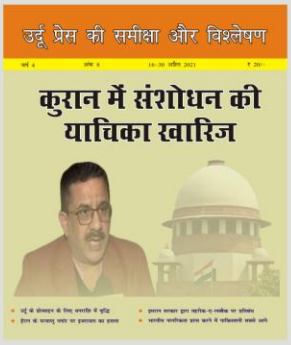

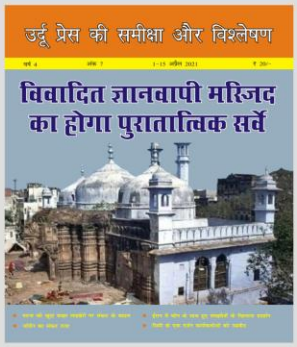

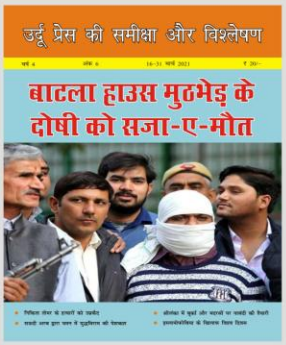

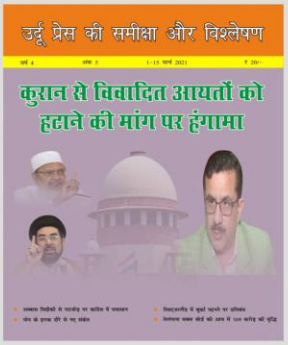

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
॥ प्रदीपवेम जगत् सर्वम् ॥
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26524018 • फैक्स : 011-46089365
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in